भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3966

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

21 श्रावण, 1948 (शक)

विदेशी एआई मॉडल पर निर्भरता

3966. श्री देवेश शाक्यः
श्री नीरज मौर्यः
श्री लालजी वर्माः
श्रीमती रुचि वीराः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय कंपनियों, स्टार्टअप और उपभोक्ताओं द्वारा विदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेवाओं के उपयोग के लिए अमेरिकी और अन्य विदेशी कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) सेवा प्रदाताओं को विदेशी मुद्रा के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 32,000 करोड़ रुपये (4 बिलियन अमरीकी डालर) का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी एआई मॉडल और क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना पर बढ़ती निर्भरता के बावजूद बजट 2026-27 में इंडियाएआई मिशन के लिए 1,000 करोड़ रुपये और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए 4,741.51 करोड़ रुपये की सीमित राशि आवंटित करने के क्या तार्किक कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान आवंटन भारत को वैश्विक एआई दौड़ में अग्रणी के रूप में स्थापित करने और स्वदेशी बड़े भाषा मॉडल और एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना के विकास के लिए गूगल, ओपनएआई, एनवीडिया आदि जैसी वैश्विक एआई दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(घ) क्या सरकार का वैश्विक एआई कंपनियों के साथ मिलकर स्वदेशी वृहद भाषा मॉडलों, एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता अथवा पूरक बजटीय प्रावधान प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आंवला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के युवाओं, स्टार्टअप और उद्योगों के लिए स्वदेशी कृत्रिम प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यनीति प्रौद्योगिकी के उपयोग का लोकतंत्रीकरण करने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत केंद्रित चुनौतियों का समाधान करना और सभी भारतीयों के लिए आर्थिक और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

सरकार एआई अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सीमित घरेलू क्षमताओं से जुड़े जोखिमों से अवगत है, और एआई मूल्य श्रृंखला में तकनीकी संप्रभुता का निर्माण करने के लिए इंडियाएआई मिशन के तहत एक बहु-आयामी और सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाया है।

इंडियाएआई मिशन

सरकार ने 7 मार्च 2024 को पांच वर्ष की अवधि में 10,371.92 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य किफायती एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल, एआई-रेडी डेटासेट, एआई एप्लीकेशन, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, प्रतिभा विकास एवं सुरक्षित और भरोसेमंद एआई को शामिल करते हुए एक व्यापक स्वदेशी एआई इकोसिस्टम का निर्माण करना है। इन पहलों का उद्देश्य स्वदेशी एआई समाधानों के विकास और अंगीकरण को बढ़ावा देना, तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और विदेशी एआई सेवाओं पर निर्भरता को उत्तरोत्तर कम करना है।

(ख): इंडियाएआई मिशन और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत बजटीय आवंटन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जो विभिन्न मिशन/कार्यक्रम घटकों के कार्यान्वयन कार्यक्रम और आवश्यकताओं के अनुरूप है।

(ग): भारत की एआई रणनीति 300 बिलियन डॉलर के वार्षिक राजस्व और 60 लाख मजबूत कार्यबल के साथ भारत के जीवंत आईटी क्षेत्र पर आधारित है। इंडियाएआई मिशन के तहत, स्वदेशी बड़े भाषा मॉडल और एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

स्वायत्त मॉडल:

समर्थन के लिए 20 स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल प्रस्तावों की पहचान की गई है, जिसमें 12 बड़े मल्टीमॉडल मॉडल और 8 लघु भाषा मॉडल शामिल हैं। पहले से लॉन्च किए गए उल्लेखनीय आउटपुट में शामिल हैं:

- **सर्वम एआई** (सर्वम 30बी/105बी, इंडस)
- **भारतजेन** (परम2 17बी टेक्स्ट, पत्रम 7बी वीएलएम, श्रुतम-2 एएसआर)
- **Gnani.एआई** (5B स्पीच टू स्पीच)
- **'वर्या'** (इमेज एंड टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन)
- **अवतार** (वर्या 14बी डिस्टिल्ड वीडियो-जेन)
- **न्यूरोडीएक्स** (मनस 1 40 एम और 400 एम: न्यूरोलॉजिकल स्क्रीनिंग)
- **जेनटीक** (ब्रह्मएआई 1B टोकनाइज़र सूट)
- **शोध एआई** (1.6B मल्टी-स्केल फिजिक्स प्रोटोटाइप, एजेंटिक टूल कॉलिंग फ्रेमवर्क)

कम्पयूट :

- 15 कंप्यूट सेवा प्रदाताओं को चार राउंड में सूचीबद्ध किया गया है।
- सब्सिडी वाले कंप्यूट सपोर्ट के लिए 237 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 93.18 लाख जीपीयू घंटे स्वीकृत किए गए हैं।
- एनआईसी डेटा सेंटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली में लगभग 1.1 ईएफएलओपीएस के उच्च-प्रदर्शन एआई कंप्यूट सिस्टम के लिए एक खरीद आदेश जारी किया गया है।

अनुप्रयोग विकास:

- 11 राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन/नवाचार चुनौतियां शुरू की गईं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में 20 एआई समाधान नियोजित किए गए हैं।

सुरक्षित और विश्वसनीय एआई:

- पूर्वाग्रह शमन, मशीन अनलर्निंग, गोपनीयता संरक्षण एआई, एल्गोरिदम ऑडिटिंग और व्याख्यात्मकता को संबोधित करने वाली 13 परियोजनाओं का चयन किया गया है।

(घ): आज की तारीख तक, इंडियाएआई मिशन के स्वीकृत परिव्यय से परे अतिरिक्त वित्तीय सहायता या पूरक बजटीय प्रावधान के लिए कोई प्रस्ताव औपचारिक रूप से अनुमोदित या अधिसूचित नहीं किया गया है।

(ङ): सरकार ने देश के युवाओं, स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए स्वदेशी एआई समाधान विकसित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

<u>उत्कृष्टता केंद्र:</u>

- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 58 एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 22 को अब तक 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मंजूरी दी गई है और शुरू किया गया है।

<u>प्रतिभा विकास:</u>

- 178 संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों में 686 फेलोशिप प्रदान की गई।
- सभी के लिए युवा एआई कार्यक्रम 26.5 लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा पूरा किया गया।

<u>इंडियाएआई लैब्स:</u>

- भारत में 27 डेटा और एआई लैब स्थापित किए गए हैं, जो 3,500 से अधिक छात्रों के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करते हैं।
- आईटीआई/पॉलिटेक्निकों में स्थापना के लिए 188 अतिरिक्त प्रयोगशालाओं की पहचान की गई है।

ये उपाय इंडियाएआई मिशन के तहत अखिल भारतीय स्तर पर लागू किए जाते हैं; इन योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ और परिणाम आंवला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित व्यक्तिगत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के स्तर पर अलग-अलग नहीं दिखाए जाते हैं।

*****